

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 62]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च 2017— फाल्गुन 12, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 2017 (फाल्गुन 12, 1938)

क्रमांक-2220/वि. स./विधान/2016 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2017 (क्रमांक 2 सन् 2017) पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 2 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2017

वित्तीय वर्ष 2016-2017 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम. 1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र.-1) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.
- वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए राज्य की संचित निधि में से 12,50,41,69,095 रुपये का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2017 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए एक हजार दो सौ पचास करोड़ एकतालीस लाख उन्हत्तर हजार पंचानवे मात्र रुपये होता है उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं एवं प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.
- विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)		(3)	
		रुपये	रुपये	रुपये
03	पुलिस	राजस्व		
		21,79,00,000	0	21,79,00,000
		पूंजी		
		4,40,00,000	0	4,40,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी		
		60,00,00,000	0	60,00,00,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व		
		70,00,00,000	0	70,00,00,000
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व		
		1,93,79,25,000	0	1,93,79,25,000
10	वन	राजस्व		
		400	0	400
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी		
		10,00,00,000	0	10,00,00,000
13	कृषि	राजस्व		
		10,36,37,000	0	10,36,37,000

(1)	(2)	(3)	रुपये	रुपये	रुपये
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	36,99,60,000	0	36,99,60,000
16	मछली पालन	राजस्व	2,58,20,000	0	2,58,20,000
17	सहकारिता	राजस्व	24,85,00,000	0	24,85,00,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	0	3,26,195	3,26,195
		पूंजी	100	0	100
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	पूंजी	100	0	100
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	100	0	100
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	100	0	100
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	3,30,00,000	14,10,000	3,44,10,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	2,92,00,000	0	2,92,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	14,66,71,000	0	14,66,71,000
		पूंजी	4,58,00,000	0	4,58,00,000
37	पर्यटन	राजस्व	4,29,00,000	0	4,29,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	पूंजी	11,11,22,000	0	11,11,22,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	45,67,83,400	0	45,67,83,400
		पूंजी	4,38,10,61,000	0	4,38,10,61,000
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	3,53,22,000	0	3,53,22,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	35,68,87,400	0	35,68,87,400
		पूंजी	47,79,56,100	0	47,79,56,100
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	100	0	100
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	100	0	100

(1)	(2)	(3)		
		रुपये	रुपये	रुपये
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व 79,37,59,000 पूंजी 9,91,95,000	0 0	79,37,59,000 9,91,95,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व 76,44,21,000	0	76,44,21,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व 37,95,58,000	0	37,95,58,000
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व 10,54,000	0	10,54,000
योग -		राजस्व 6,64,32,98,200 पूंजी 5,85,91,34,700	17,36,195 0	6,64,50,34,395 5,85,91,34,700
वृहद योग		12,50,24,32,900	17,36,195	12,50,41,69,095

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 2 मार्च, 2017

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

“संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित”

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.